

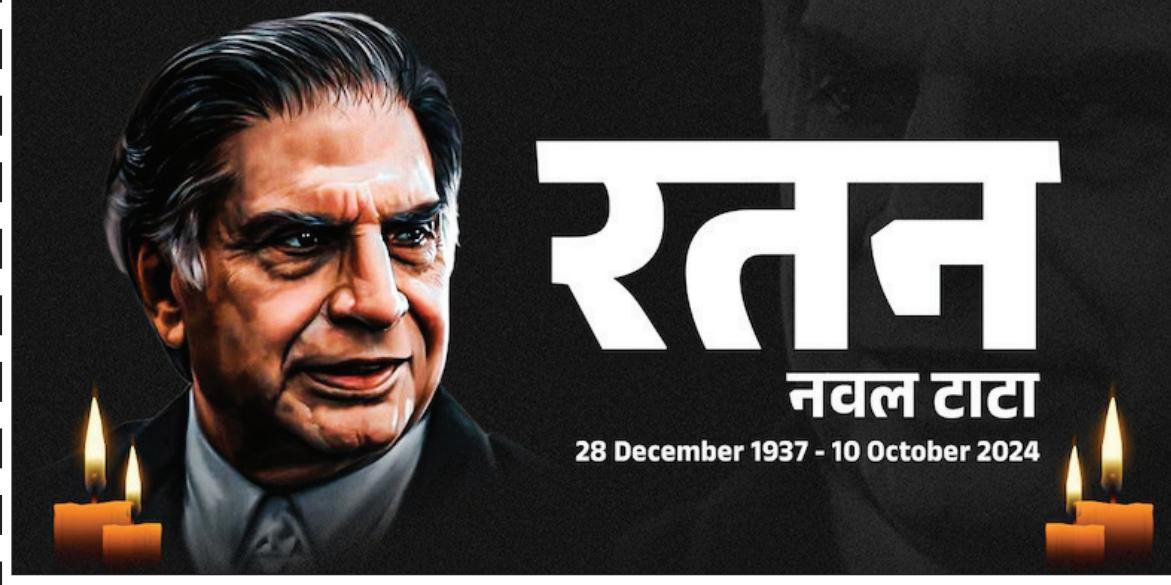
अखंड भारत संदेश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज शुक्रवार 11 अक्टूबर 2024

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को द्रुतगति प्रदान करने हेतु कियायोग आश्रम एवं अनुसंधान आश्रम की अनुपम भेट



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है "श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी उद्योगपति, एक दयालु आमा और एक असाधारण इन्सान है। उन्होंने भारत के सभसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को व्यापार नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरमूले से कहीं आगे तक गया।

उन्होंने अपनी विनियोग, द्यावतुगा और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अद्भुत प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई।"

रतन टाटा के निधन पर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, "मैं उनसे पहली बार तब मिता था जब मैं सरकार में एक तरह से मध्यम स्तर पर था। उस समय, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ईड्डों को शुरूआत की थी।

वह एक सेवा व्यक्ति के रूप में स्वाभाविक परसे थे जो इनका नेतृत्व करने वाले थे। उन्होंने व्यक्ति के रूप में हम एक साथ मिलकर काम करते थे, साथ में अमेरिका की यात्रा करते थे। वह वाताने में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। मुझे लगता है कि अगर आप आज भावातारों, स्तोह, समाज के प्रवाह को देखें, तो मुझे उद्योग जगत में ऐसा कोई व्यक्ति याद नहीं आता जिसने बहुत व्यापक वर्ष के लोगों में इस तरह की भवना बढ़ा थी। मेरा मतलब है, इसे वास्तव में गाढ़ीय क्षति के रूप में देखा जाता है। वह अपने समय से आगे के व्यक्ति थे। उन्होंने टाटा समूह को एक तरह से विदेश में ले गए।"

रतन टाटा के निधन पर केंद्रीय मंत्री साबनदार सानोवाल ने कहा, "शेर के महान संघर रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने अपने जीवन में योगदान दिया और देश के विकास को दिशा देने के लिए जो कदम उठाए, इतिहास उन्हें हमेशा बहुत समान के साथ याद रखेगा।"

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, "रतन टाटा ने अपने अधिक परिश्रम और प्रगतिशील व्यक्तिगत से भारतीय उद्योग जगत को नई ऊँचाइयां दीं, जिनका विकास और मानवता की सेवा के क्षेत्र में रतन टाटा ने जो अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया है, वह सदियों तक प्रेरणा देता रहा। देश को उनकी कमी हमें खलीगी। रतन टाटा के परिवार और वाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संदेशान्तरण, इश्वर उन्हें आपने श्रीरामों में स्थान दें।"

अभिनेता रजनीकांत ने कहा, "एक महान दिमाग आइकन जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता और जुनून से भारत को वैश्विक मानविक पर स्थापित किया। वह व्यक्ति जिसने हजारों उद्योगपतियों को प्रेरित किया। वह व्यक्ति जिसने कई पीड़ियों के लिए लाखों योगदान दी है। वह व्यक्ति जिसे सभी यार करते थे और समाज देते थे। उन्हें मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि, मैं इस महान आत्मा के साथ विदेश हर पल को हमेशा सभी कर रखूँगा। भारत का एक सच्चा सपूत्र अब हमारे बीच नहीं रहा। शरि से विश्वास करें।"

दिल्ली में कांग्रेस की हुई बड़ी बैठक, बन गया मार्ट्रप्लान

नई दिल्ली। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद आज कांग्रेस ने दिल्ली में सांसद बैठक बुलाई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मलिकार्जुन खगोली और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बता दे बैठक में चुनाव नतीजों को लेकर एक फैटेट पार्टी डिझाइन कमेटी के गठन को ही छाड़ी दी गई। बैठक के बाद पार्टी नेता अंजय माकन ने इस मीटिंग में जानकारी साझा की। माकन ने कि हरियाणा चुनाव के नतीजों को अप्रलियत बताया और



कहा कि एग्जिट पोल्स और चुनाव नतीजों में जानी-नासान का फर्क था। माकन ने आगे बताया कि

मीटिंग में चुनाव आयोग को लेकर भी बात हुई जिसके लिए लोकर पार्टी आगे अपील और कार्रवाई करेगी।

नेशनल कॉफ्रेंस को मिला 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन, उमर अब्दुल्ला चुने गए विधायक दल के नेता

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉफ्रेंस ने 90 सदस्यीय विधानसभा कांस्टेंटों के साथ बहुत के आंकड़े के साथ 42 सीटें जीती हैं।

नेशनल कॉफ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस को छह सीटें मिली हैं। हालांकि, 4 स्वतंत्र विधायकों के समर्थन से, एनसी को अपने दम पर बहुमत मिल गया है और वह कांग्रेस पर भरोसा करने के लिए बाध्य नहीं है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित करने के बाद, चार निवालीय विधायकों का विधायक दल का नेशनल कॉफ्रेंस के प्रभावधार्मी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधायक दल की एक बैठक हुई जहाँ

एनसी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को संवर्समति से नेशनल कॉफ्रेंस के विधायक दल का प्रभुय चुना गया। फारस्क अब्दुल्ला ने कहा कि

विधायक दल की एक बैठक हुई जहाँ

नेशनल कॉफ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस को

छह सीटें मिली हैं। हालांकि, 4 स्वतंत्र विधायकों के समर्थन से, एनसी को अपने

विधायक दल के साथ 42 सीटें जीती हैं।

नेशनल कॉफ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस को

छह सीटें मिली हैं। हालांकि, 4 स्वतंत्र विधायकों के समर्थन से, एनसी को अपने

विधायक दल की एक बैठक हुई जहाँ

नेशनल कॉफ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस को

छह सीटें मिली हैं। हालांकि, 4 स्वतंत्र विधायकों के समर्थन से, एनसी को अपने

विधायक दल की एक बैठक हुई जहाँ

नेशनल कॉफ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस को

छह सीटें मिली हैं। हालांकि, 4 स्वतंत्र विधायकों के समर्थन से, एनसी को अपने

विधायक दल की एक बैठक हुई जहाँ

नेशनल कॉफ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस को

छह सीटें मिली हैं। हालांकि, 4 स्वतंत्र विधायकों के समर्थन से, एनसी को अपने

विधायक दल की एक बैठक हुई जहाँ

नेशनल कॉफ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस को

छह सीटें मिली हैं। हालांकि, 4 स्वतंत्र विधायकों के समर्थन से, एनसी को अपने

विधायक दल की एक बैठक हुई जहाँ

नेशनल कॉफ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस को

छह सीटें मिली हैं। हालांकि, 4 स्वतंत्र विधायकों के समर्थन से, एनसी को अपने

विधायक दल की एक बैठक हुई जहाँ

नेशनल कॉफ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस को

छह सीटें मिली हैं। हालांकि, 4 स्वतंत्र विधायकों के समर्थन से, एनसी को अपने

विधायक दल की एक बैठक हुई जहाँ

नेशनल कॉफ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस को

छह सीटें मिली हैं। हालांकि, 4 स्वतंत्र विधायकों के समर्थन से, एनसी को अपने

विधायक दल की एक बैठक हुई जहाँ

नेशनल कॉफ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस को

छह सीटें मिली हैं। हालांकि, 4 स्वतंत्र विधायकों के समर्थन से, एनसी को अपने

विधायक दल की एक बैठक हुई जहाँ

नेशनल कॉफ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस को

छह सीटें मिली हैं। हालांकि, 4 स्वतंत्र विधायकों के समर्थन से, एनसी को अपने

विधायक दल की एक बैठक हुई जहाँ

नेशनल कॉफ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस को

छह सीटें मिली हैं। हालांकि, 4 स्वतंत्र विधायकों के समर्थन से, एनसी को अपने

विधायक दल की एक बैठक हुई जहाँ

नेशनल कॉफ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस को

छह सीटें मिली हैं। हालांकि, 4 स्वतंत्र विधायकों के समर्थन से, एनसी को अपने

विधायक दल की एक बैठक हुई जहाँ

नेशनल कॉफ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस को

छह सीटें मिली हैं। हालांकि, 4 स्वतंत्र विधायकों के समर्थन से, एनसी को अपने

विधायक दल की एक बैठक हुई जहाँ

<p

सम्पादकीय

जम्मू-कश्मीर में उम्रीदों की सरका

हिंसा और राज्य समर्थित दमन के 10 वर्षों के बाद जम्मू-कश्मीर कांग्रेस व नेशनल कांफ्रेंस की गठबन्धन वाली सरकार बनी स्वाभाविकतः लोगों के मन में उसे लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। ये अब केवल उस राज्य में रहने वालों को ही नहीं वरन् देश-विदेश में वाले हर उस व्यक्ति की हैं जो उस राज्य की स्थिति को लेकर दुश्मन 5 अगस्त, 2019 को भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने सौंपे के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर का विशेष राजदर्जा छोन लिया था। वहां आतंकवाद के सफाये के नाम पर नाया पर जुल्म ढाये गये। पिछले एक दशक तक प्रदेश प्रतिनिधित्व फैला रहा। भाजपा का एक नुमाइंदा प्रशासक बनकर राज्य को हांकता इसे लेकर जो बड़े-बड़े दावे भाजपा और केन्द्र सरकार ने किये कुछ भी पूरे नहीं हुए। उल्टे जम्मू-कश्मीर विकास की दौड़ में पिछला चला गया। नवी सरकार से लोगों को उम्मीद है कि वह लोगों के नाया पर मरहम लगाये और सूबे को विकसित करे। हिंसा और नफरत खत्म कर वहां कश्मीरियत की वह इवारत फिर से लिखे जा सकती है, जिसे पिछले बरसों में पूर्णतः मिटाने की कोशिश की गई। इस प्रांत में रहने वालों के प्रति भाजपा की घृणा जगजाहिर है। नफरती भावना के चलते 370 समाप्त तो कर दी गयी लेकिन इसके बाद यह नहीं पता चल सका कि अब क्या करना चाहिया था कि अनुच्छेद 370 ही सभी समस्याओं की जड़ है। इसके हटते ही कश्मीर में शांति और विकास की गंगा बहने लगेगी। साफ था कि केन्द्र सरकार की दिलचस्पी जम्मू-कश्मीर के लोगों में बल्कि यहां के व्यवसायी और यहां की जमीनों को हड़पने में है। लगे कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यहां के प्रमुख कारोबार अपने व्यक्तिगत कामों को सौंपना चाहते हैं।

सम्भवतः बाद में उन्हें और उनके दोस्तों को एहसास हुआ होगा कि इस प्रांत को सम्भालना वैसा आसान नहीं है। जैसा वे सोच रहे थे। हकीकत यह है कि धारा 370 के खत्म करने से यहां कुछ भी हासिल नहीं हुआ। नागरिकों का जो नुकसान हुआ वह अपनी जगह पर है। जम्मू-कश्मीर की जो नयी सरकार बनने जा रही है, उसे कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। पहली तो यह कि सरकार को गिराने की हरसम्भव कोशिश होगी क्योंकि यह भाजपा की नाक का सवाल है और ध्वनीकरण का उपकरण भी। प्रचारित यह किया गया था कि अनुच्छेद 370 हटने से यहां के नागरिक खुश हैं और खुशहाली बहाल हुई है। सत्ता पाने के लिये जम्मू में 5 सीटें बढ़ाई भी गईं। फिर, एक अशांत सीमा से लगे होने के कारण केन्द्र के माध्यम से भाजपा द्वारा प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की भरपूर कोशिश होंगी। जम्मू-कश्मीर के जो हालात हैं, ऐसे अवसर मिल सकते हैं। न हों तो बनाये जा सकते हैं। भाजपा का कुछ्यात 'ऑपरेशन लोटस' फिर से सक्रिय करने के भी प्रयास होंगे। हालांकि नयी विधानसभा में जो दलीय स्थिति है, उसके चलते फिलहाल उसकी गुजाइश नहीं है परन्तु भाजपा इस सरकार को गिराने के रास्ते तैयार करती ही रहेगी।

जम्मू-कश्मीर में नेशनल कान्फ्रेंस-कांग्रेस की जीत के साथ बदलाव की जमीन तैयार

- सुशील कुट्टी
जमू-कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों के
लिए 873 उमीदवारों ने चुनाव मैदान में
अपना भाष्य आजमाया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक
पार्टी ने हार मान ली। महत्वपूर्ण बात यह है
कि एनसी-कॉर्पस गठबंधन को जीत के साथ
जमू-कश्मीर में बहुत कुछ बदलने वाला है।
एक तो यह कि भाजपा के पंख कट गये हैं।
न उपराज्यपाल अब 'राजा' की तरह होगे
और न ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
'पापा' नहीं रहा।

आतंकवादियों द्वारा मारे जाने और बच जाने के बाद भी आज उनका जीवन कम नारकीय नहीं हो गया है। उस समय भी नहीं जब पत्थरबाजी एक दैनिक घटना थी। स्वतंत्र उम्मीदवार, जिन पर भाजपा ने भरोसा किया था, भी हार गये। नेशनल कॉन्फ्रेंस/कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में पीड़ीपी उम्मीदवारों को हराया, लेकिन इसने अब्दुल्ला परिवार को महबूबा की ओर दोस्ताना हाथ बढ़ाने से नहीं रोका। जीत में उदारता! परिणाम लगभग ऐसे थे जैसे पीड़ीपी ने चुनाव ही नहीं लड़ा था। दलितजन मानी तो, मानी परिवार के मह

कर दिया गया। जम्मू-कश्मीर के लाखों लोग इन चुनावों का इंतजार कर रहे थे। चुनाव परिणाम से पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकास कार्यों' से जम्मू-कश्मीर के अधिसंच्छ लोग प्रभावित नहीं हुए। जम्मू-कश्मीर को उसके 'राज्य-दर्जा' में वापस लाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की समय सीमा भी है। समय सीमा का पालन करना होगा। बहाने बर्दाश्ट नहीं किये जायेंगे। जम्मू-कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में बना हुआ है। ऐसी दबी हुई खबरें हैं कि लद्दाख को जम्मू-कश्मीर में तामाज़ लौटाने में कोई आगाज़ नहीं

सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर के अब सभी को राहत मिली कि चुनाव शार्टपूर तरीके से संपन्न हो गये। वास्तव में, यह केवल की उपलब्धि थी। सभी मतगणना केंद्रों पर तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतगणना की गयी। कोई नहीं कह सकता कि कश्मीर में कब विस्फोट हो जाये। जम्मू-कश्मीर चुनाव में पाकिस्तान की दिलचस्पी है। आतंकवाद, उग्रवाद और सीमा पार से घुसपैठ सभी इस 'मित्रवत पड़ोसी' वाली बदौलत हैं। सबाल यह है कि जम्मू-कश्मीर में नागरिक सरकार की वापसी से पाकिस्तान के साथ असंतुष्टिकारी या अनाशंकित मानधंधे पर

इलंजा मुफ्ता ता मुफ्ता पारवार के गढ़ बिजबेहरा में भी हार गयी। यह कहा गया कि विधानसभा चुनाव 2014 के बाद से जम्मू और कश्मीर के पहले चुनाव थे। साथ ही, जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किये जाने के बाद भी ये पहले चुनाव थे। खास बात यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद यह पहला चुनाव था। एरिजट पोल ने त्रिंकु सदन की भविष्यवाणी की थी, लेकिन यह पता चला कि जम्मू-कश्मीर के मतदाताओं की धारणा बिल्कुल अलग थी। सुबह 8 बजे से ही बोटों की गिनती शुरू हो गयी थी और तभी से यह स्पष्ट था। हिंसा की कोई घटना नहीं हुई, मानो तथाकथित 'उग्रवादी' भी यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। छह साल के अंतराल के बाद एक नयी सरकार चुनी जानी थी। 20 जून, 2018 को पीडीपी-भाजपा शासन का पतन हो गया केशमर म वापस लाटन म काइ आपात नहा होगा।

कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय की समय-सीमा का पालन किया जाये। इंडिया गठबंधन, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस एक घटक है, भी इस पर विचार करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, जिसकी अब आवश्यकता नहीं है। अब्दुल्ला ने कहा कि उपराज्यपाल को पांच आरक्षित सीटों पर यादचिक लोगों को नामित करने का कोई अधिकार नहीं है। एनसी-कांग्रेस गठबंधन ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की योजना बनाई है। पांच नामित सदस्यों के आने से विधानसभा की संख्या 95 हो जायेगी और बहुमत का आंकड़ा 48 हो जायेगा।

क साथ आधाराकांक्ष या अन्यथा संघर्ष क्या असर पड़ेगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ही चाहते हैं कि भारत-पाक वार्ता फिर से शुरू हो। मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार कम से कम फिलहाल पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के संबंध रखने के खिलाफ है। केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच टकराव होना तय है। राजनीति के लोग और घाटी के लोग विरोध करेंगे अलगाववादी अपनी मांगों और विरोध वें अपने तरीके के साथ प्रतिशोधात्मक तरीके परिवर्तन के लिए उभर सकते हैं।

अनुच्छेद 370 एनसी-कांग्रेस गठबंधन सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। बेशक, जब तक इंडिया गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की योजना बनाई है। पांच नामित सदस्यों के आने से विधानसभा की संख्या 95 हो जायेगी और बहुमत का आंकड़ा 48 हो जायेगा।

A collage of four young children. From left to right: a girl in a white lab coat and a stethoscope around her neck; a girl in a school uniform (white shirt and tie) holding a large beige folder; a boy with dark curly hair in a yellow and white striped t-shirt, smiling broadly; and a boy with light-colored hair, partially visible, with his hands near his face.

बालिकाओं के खिलाफ सामाजिक अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे

खिलाफ सामाजिक प्रथा को जन्म दिया है औं की स्थिति को बदल दिया है। अमर्तौर पर वर्ते हैं की लड़कियां वर्च करती हैं जिसके इकियों को बहुत से धूप हत्या, दहेज के नम से पहले या बाद में याओं या महिलाओं को ये मुद्रे समाज से बहुत ने की आवश्यकता है। -अफगानिस्तान आदि एवं महिलाओं पर हो बर्बरता, शोषण की शगूल दिखाई देते हैं में आए दिन नाबालिग कर वृद्ध महिलाओं तक छेड़छाड़, बलात्कार, आएं पर क्यों मौन साध देश में जहां नवरात्र में केया जाता है, लोग पर बुलाकर उनके पैर उन्हें यथासंभव उपहार को प्रसन्न करने का वहीं इसी देश में बेटियों पार दिये जाने एवं नारी अस्तित्व को नौचने की इन दोनों कृत्यों में कोई नहीं बल्कि गजब का बाईं देता है। बालिकाओं के अस्तित्व लिये जागरूकता एवं बवजूद बालिकाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे में भी बालिकाओं की स्थिति, कभूण हत्या की बढ़ती घटनाएं, लड़कों की तुलना में लड़कों की बढ़ती संख्या तलाक के बढ़ते मामले, गांवों बालिका की अशिक्षा, कुपोषण शोषण, बालिकाओं की सुरक्षा बालिकाओं के साथ होने वालात्कार की घटनाएं, अश्वील हरावे और विशेष रूप से उनके खिलाफ हावाले अपराधों पर प्रभावी चर्चा कठोर निर्णयों से एक सार्थक वातावर का निर्माण किये जाने की अपेक्षा क्योंकि एक टीस-सी मन में उठती कि आखिर बालिकाओं कब तक की वस्तु बनी रहेगी? उसका जी कब तक खतरों से घिरा रहेगा बलात्कार, छेड़खानी, धूप हत्या उद्देश दहेज की धथकती आग में वह तक भस्म होती रहेगी? कब तक उस अस्तित्व एवं अस्तित्व को नौचा जरहेगा? दरअसल छोटी लड़कियों महिलाओं की स्थिति अनेक मुस्लिम और अफ्रीकी देशों में दयनीय जबकि अनेक मुस्लिम देशों महिलाओं पर अत्याचार करने वालों लिये सख्त सजा का प्रावधान अफगानिस्तान-तालिबान का अपहृत है। वहां के तालिबानी शासकों महिलाओं को लेकर जो फरमान जकिए हैं वो महिला-विरोधी होने के सिद्धि को दहलाने वाले हैं। दुनिया बड़ी शक्तियों को इन बालिकाओं स्वतंत्र अस्तित्व को बचाने के लिये

— 2 —

ମେଲିର କାନ୍ଦିର କାନ୍ଦିର କାନ୍ଦିର କାନ୍ଦିର

लद्दाख से उठी हिमालय की आवाज

- कुलभूषण उपमन्त्र

A photograph showing a large group of people marching in a protest. Many individuals are wearing white shawls or cloaks over their clothing. In the background, a large banner is visible with text in English and Hindi. The banner includes the words "PEOPLES MARCH AGAINST 13TH SCHEDULE FOR LADAKH", "DELHI CHALO LEH YATRA", and "Ladakh is part of India". The scene appears to be outdoors in a public space.

दिल्ली के राजघाट (गांधी समाधि) पहुंचने की उम्मीद रखते थे। बरसों से पदयात्रा भारत में जनहित, आध्यात्मिक संदेश पहुंचाने और समाज को जगाने का सशक्त माध्यम रहा है। सोनम जी की यात्रा को मार्ग में जगह-जगह मिला समर्थन साबित कर रहा है कि पदयात्रा आज भी शुद्ध जनहित और आध्यात्मिक संदेश फैलाने का सशक्त माध्यम है, जिसकी प्रासारणी असर्विद्य है, बशर्ते यात्रा का लक्ष्य स्वार्थ-जनित न हो। हिमाचल और गढ़वाल की 'हिमालय बचाओ संपर्क वाहन यात्रा' के दौरान भी सवाल उठे थे कि 'जब हिमालय तुम्हें बचा रहा है तो तुम हिमालय को बचाने वाले कौन होते हो,' तो जवाब होता था कि हिमालय की हमें बचाने की शक्ति हमारी गलत विकास की गतिविधियों और हमारे लालच के कारण अति-दोहन के चलते नष्ट हो रही है। हिमालय को बचाने का अर्थ है, हिमालय की वाय को शुद्ध करने महत्वपूर्ण है। मनुष्य समाज और प्रकृति-तन्त्र का संतुलित रिश्ता ही परिस्थितिकीय संतुलन का आधार है। हमारा आज का विकास का मॉडल इस तत्व की अनदेखी कर रहा है। हम सोचने लगे हैं कि सभी समस्याओं के समाधान इंजीनियरिंग और तकनीकी से मिल सकते हैं, किन्तु ऐसा है नहीं। हम पानी का एक कतरा, हवा का एक श्वास, मिट्टी का एक ढेला, प्रकृति के तत्वों का प्रयोग किए बिना बना नहीं सकते। जिन्दा रहने के लिए हवा, पानी और भोजन ही सबसे बुनियादी जरूरतें हैं। हमारा विकास इन्हीं पर आधात कर रहा है। ग्लोशियर पिघल रहे हैं, जिससे नदियों के अस्तित्व पर खतरा आ गया है। वे मौसमी होकर रह जाएंगी। मिट्टी हमारी रासायनिक खेती की पद्धति द्वारा जहरीली होती जा रही है, वही जहर हमारे खाद्य पदार्थों में पहुंच रहे हैं। हवा को सभ्यता का धुआं जहरीला कर रहा है तो संकट जिन्दा रहने पर आने वाला है। सबसे संवेदनशील परिस्थिति-तन्त्र की 'छठी अनुसूची' में डालने का मांग है। इस अनुसूची में डाले जाने से प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने में स्थानीय समाजों की भूमिका सशक्त होगी और सरकार को भी संसाधनों के तरक्की पूर्ण दोहन के लिए व्यवस्था बनाने में आसानी होगी। कई दशकों से हिमालय में वैकल्पिक विकास का मॉडल अपनाने की मांग हो रही है। 'योजना आयोग' के समय से ही यह मुद्दा उठता रहा है, किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला है। लोगों को छिपटुट संघर्षों के कारण कहीं अपनी बात मनवाने में सफलता मिली भी है, किन्तु असली समाधान तो वैज्ञानिक समझ से हिमालय की संवेदनशील परिस्थितिकी के अनुरूप विकास मॉडल लागू करने से ही होगा। इसके लिए 'पांचवीं' और 'छठी अनुसूची' कुछ संरक्षण तो दे ही सकंगी। तो क्यों न ट्रांस-हिमालय को 'छठी अनुसूची' और शेष हिमालय को 'पांचवीं अनुसूची' में डालकर हिमालय को मुख्यधारा के विकास की विनाशकारी दौड़ से

